



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13 ]  
No. 13]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 21, 2003/ज्येष्ठ 31, 1925  
NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 21, 2003/JYAISTHA 31, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जून, 2003

का०नि०आ० 70.—रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि जम्मू-कश्मीर राज्य के रजौरी जिले में नोशेरा तहसील, नादपुर गांव में स्थित गोलाबारूद केन्द्र-251 के निकट होने के कारण इसे भवनों तथा अन्य बाधाओं से मुक्त रखे जाने के उद्देश्य से इसके उपयोग तथा अधिभोग पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।

2. उपर्युक्त भूमि से संबंधित रेखाचित्र नक्शे का निरीक्षण उपायुक्त, जिला रजौरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू-कश्मीर राज्य में रक्षा संकर्म अर्थात् गोलाबारूद केन्द्र-251, नोशेरा तहसील, नादपुर गांव, जिला रजौरी की बाहरी परिधि से 1000 गज की दूरी के भीतर के क्षेत्र में आने वाली समस्त भूमि।

[रक्षा मंत्रालय सं० ए/51491/एल डब्ल्यू (उत्तर)/539 एस]

ललित चौहान, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 10th June, 2003

S.R.O. 70.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose restrictions specified in clause (c) of Section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule given below, being land lying in the vicinity of Ammunition Point-251 at Village Nadpur, Tehsil Nowshera, District Rajouri in the State of Jammu and Kashmir in order that the said land may be kept free from building and other obstructions.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the Office of Deputy Commissioner, Rajouri District.

### SCHEDULE

All the land comprised in the area lying within the distance of 1000 yards from the outer perimeter of the Works of Defence, namely Ammunition Point-251 at Village Nadpur, Tehsil Nowshera, District Rajouri in the State of Jammu and Kashmir.

[Ministry of Defence No. A/51491/LW(North)/539S]

LALIT CHAUHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 जून, 2003

का०नि०आ० 71.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सेना आर्डनेंस कोर, आर्डनेंस अधिकारी सिविलियन (भंडार) भर्ती नियम, 1996 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना की निम्नतर विरचनाओं में आर्डनेंस अधिकारी सिविलियन (भंडार) और ज्येष्ठ आर्डनेंस अधिकारी सिविलियन (भंडार) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना आर्डनेंस कोर, समूह "ख" राजपत्रित आर्डनेंस अधिकारी सिविलियन (भंडार) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

1-1. पद का नाम	: ज्येष्ठ आर्डनेंस अधिकारी (भंडार)
2. पदों की संख्या	: 60*
	2003
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	: साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख", राजपत्रित अननुसचिवीय
4. वेतनमान	: 7500-250-12000 रु.
5. चयन सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	: अचयन
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	: लागू नहीं होता

7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल : नहीं  
सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम  
30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए : लागू नहीं होता  
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए : लागू नहीं होता  
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत  
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
10. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : लागू नहीं होता
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा : प्रोन्नति  
या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न  
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की : प्रोन्नति :—ऐसा आर्डनेंस अधिकारी सिविलियन (भंडार) जिसने उस श्रेणी में तीन  
दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/  
आमेलन किया जाएगा वर्ष नियमित सेवा की है।  
टिप्पण : 1—नए सृजित 60 पदों को सम्यक्त गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा  
विद्यमान पदधारियों की उपयुक्तता के निर्धारण के पश्चात् आर्डनेंस अधिकारी सिविलियन  
(भंडार) की श्रेणी में नियमित आधार पर रखकर भरा जा सकेगा। भावी रिक्तियों पर  
पश्चात्पूर्व नियुक्तियां भर्ती की उपयुक्त पद्धति द्वारा की जाएंगी।  
टिप्पण : 2—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता  
सेवा पूरी कर ली है। प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों  
के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु, यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी  
अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,  
इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,  
जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी करी ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में  
प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना : समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति :—  
1. महानिदेशक आर्डनेंस सेवा —अध्यक्ष  
2. अपर महानिदेशक आर्डनेंस सेवा (कपड़ा) आवश्यक वस्तुएं  
और प्रशासन —सदस्य  
3. मास्टर जनरल आर्डनेंस का नाम निर्देशिनी जो ले० कर्नल/  
सिविलियन स्टाफ अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो —सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।  
सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
- 
2. 1. : आर्डनेंस अधिकारी (सिविलियन भंडार)  
2. : 60\*  
2003  
\*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।  
3. : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित अननुसचिवीय  
4. : रु. 6500-200-10500

5. : चयन

6. : 30 वर्ष से अनधिक

टिप्पण-1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष शिथिलनीय।

टिप्पण-2 :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7. : नहीं

8. : आवश्यक :—

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समतुल्य।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से न्यूनतम एक वर्षीय सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा या समतुल्य।

टिप्पण : अर्हताएं/अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

वाछनीय :—

(i) कंप्यूटर कार्यक्रम में डिप्लोमा और

(ii) लेखा कर्म/सामग्री प्रबंधन/तालिका नियंत्रण में दो वर्ष का अनुभव।

9. : नहीं

10. : दो वर्ष

11. : 75% प्रोन्नति, 25% सीधी भर्ती

12. : प्रोन्नति :—ऐसा ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण :—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है। प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु, यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी करी ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

13. : समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति :—

1. महानिदेशक आर्डनेंस सेवा

—अध्यक्ष

2. अपर महानिदेशक, आर्डनेंस सेवा (कपड़ा) आवश्यक वस्तुएं और प्रशासन

—सदस्य

3. मास्टर जनरल आर्डनेंस का नाम निर्देशित जो ले० कर्नल/सिविलियन स्टाफ अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो

—सदस्य

14. : सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[ सं. ए/09513/आर.आर./ज.ओ.ओ.सी.एस./पीसी.एस.ओ./ओ.एस.-8डी./316/रक्षा(नि.) ]

वी. ए. चावड़ा, अवर सचिव

New Delhi, the 4th June, 2003

S.R.O. 71.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Army Ordnance Corps, Officer Civilian (Stores) Recruitment Rules, 1996, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Ordnance Officer Civilian (Stores) and Senior Ordnance Officer Civilian (Stores) in the lower formation of Army under Ministry of Defence, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Army Ordnance Corps, (Group 'B' Gazetted) Ordnance Officer Civilian (Stores) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification, and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Scheduled aforesaid.

**4. Disqualification.**—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or,

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

1. Name of post	: Senior Ordnance Officer Civilian (Stores)
2. Number of post	: 60* (2002)
	*Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	: General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial
4. Scale of pay	: Rs. 7500-250-12000
5. Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post	: Non-selection
6. Age limit for direct recruits	: Not applicable
7. Whether benefit of added years of service admissible	: No
8. Educational and other qualifications required for direct recruits	: Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	: Not applicable
10. Period of probation, if any	: Not applicable
11. Method of rectt. whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	: Promotion

12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made : **Promotion :**  
 Ordnance Officer Civilian (Stores) with three years regular service in the Grade.  
**Note 1 :—**The newly created 60 posts may be filled up by placing the existing incumbents on regular basis in the grade of Ordnance Officer Civilian (Stores) by a duly constituted Departmental Promotion Committee. All subsequent appointments to the future vacancies shall be made as per above method of rectt.  
**Note 2 :—**Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith in their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
13. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition : **Group 'B' Departmental Promotion Committee :—**  
 1. Director General Ordnance Services —Chairman  
 2. Additional Director General Ordnance Services (Clothing) Necessaries and Administration —Member  
 3. A Nominee of Master General Ordnance not below the rank of Lt. Col./Civilian Staff Officer —Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be considered in making recruitment : Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
- 
2. 1. : Ordnance Officer Civilian (Stores)  
 2. : 60\*  
 (2002)  
 \*Subject to variation dependent on workload.  
 3. : General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.  
 4. : Rs. 6,500-200-10,500  
 5. : Selection  
 6. : Not exceeding 30 years.  
**Note 1:** Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.  
**Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar or Lakshadweep.
7. : No  
 8. : **Essential :**  
 (i) Degree of a Recognized University or equivalent  
 (ii) Diploma in Material Management or equivalent of atleast one year duration from a recognized University/Institution.

8. : **Desirable :**

(i) Diploma in Computer Programming; and

(ii) Two years experience in Accountancy/Material Management/Inventory control.

**Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

9. : No

10. : Two years

11. : 75% Promotion  
25% recruitment12. **Promotion :** Senior Store Superintendent with three years regular service in the grade.**Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite Qualifying/Eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their Probation period for promotion to the next higher grade alongwith in their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.13. **Group 'B' Departmental Promotion Committee :**

1. Director General Ordnance Services —Chairman

2. Additional Director General Ordnance  
Services (Clothing) Necessaries and  
Administration —Member3. A Nominee of Master General Ordnance  
not below the rank of Lt. Col/Civilian  
Staff Officer —Member

14. Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[No. A/09513/RR/SROOC (S)/PCSO/OS-8D/316/D(Apptts)]

V. A. CHAVDA, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 जून, 2003

का.नि.आ. 72.—केन्द्र सरकार प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 (1948 का 56) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा प्रादेशिक सेना नियमावली 1948 में निम्नलिखित रूपांतर तथा संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को प्रादेशिक सेना (संशोधन) नियमावली 2003 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रादेशिक सेना नियमावली 1948 में नियम 20-क में "दो वर्ष की अवधि के भीतर अधिकतम दो माड्यूलस पचहत्तर दिनों से अनधिक की कुल अवधि के लिए" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"अथवा अपर महानिदेशक प्रादेशिक सेना, चार वर्ष की अवधि के भीतर 90 दिनों से अनधिक की निरंतर अवधि के लिए"

[फा. सं. 68416/पीसीटी/टीए-2/590/एसओ/र(जीएस-1)/03]

एम. एल. शर्मा, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : प्रादेशिक सेना नियमावली 1948 भारत के राजपत्र में 12 फरवरी, 1949 के सा.नि.आ. 252क के द्वारा प्रकाशित हुई थी और पिछली बार इसमें सा.नि.आ. 73 दिनांक 06 अप्रैल, 1999 द्वारा संशोधन किया गया था।

New Delhi, the 5th June, 2003

**S.R.O. 72.**—In exercise of the powers conferred by the Section 14 of the Territorial Army Act, 1948 (56 of 1948), the Central Government hereby makes the following adaptations and modification in the Territorial Army Rules 1948, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Territorial Army (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Territorial Army Rules, 1948 in rule 20-A for the words “for a total period not exceeding seventy five days in a maximum of two modules within a period of two years” the following shall be substituted, namely :—

“or Additional Director General Territorial Army, for a continuous period not exceeding ninety days, within a period of four years”

[F. No. 68416/PCT/TA-2/590/SO/D(GS-I)/03]

M. L. SHARMA, Under Secy.

Footnote:—The Territorial Army Rules, 1948 were published in Gazette of India vide S.R.O. 252A dated the 12th February, 1949 and last amended vide S.R.O. 73 dated 06 April, 99.

नई दिल्ली, 10 जून, 2003

का.नि.आ. 73.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे सम्पदा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे, अर्थात् :—

#### सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	कारखाने का नाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2	3
महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/निर्माण प्रबंधक (प्रशासन)/सहायक निर्माण प्रबंधक (प्रशासन), आर्डनेंस कारखाना नालंदा	आर्डनेंस कारखाना, नालंदा बिहार	रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन परिसरों जो उनकी अपनी अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित हैं।

[फा. सं. 4(5)/1/2003-रक्षा (निर्माण-II)]

बी. के. मल्होत्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 10th June, 2003

S.R.O. 73.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column 1 of the Table below, being Gazetted Officers of Government to be Estate Officer for the purpose of the said Act who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of public premises specified in the corresponding entry in column 3 of the said table, namely :—

TABLE

Designation of Officer	Name of the Factory	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
1	2	3
General Manager/Deputy General Manager/Works Manager (Administration)/Assistant Works Manager (Administration), Ordnance Factory, Nalanda	Ordnance Factory Nalanda, Bihar	Premises under the administrative control of the Ministry of Defence situated within the local limits of their respective jurisdiction.

[F. No. 4(5)/1/2003-D(Fy-II)]

B. K. MALHOTRA, Under Secy.